www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 295 | जौनपुर मंगलवार, 16 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जनवरी से मई तक, चीनी रेलवे ने 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया

बीजिंग, (एजेंसी)। चाइना रेलवे ग्रु के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से मई तक, चाइना रेलवे ने कुल 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया, जो साल दर साल 1.8 प्रतिशत अधिक है। औसत दैनिक लोडिंग 186300 वैगन थी, जो साल दर साल 2.8 प्रतिशत अधिक है, और 2 मई को 202400 वैगन लोड किए गए, जिसने एक दिन की लोडिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। रेलवे क्षेत्र ने चाइना मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एलायंस का लाभ उठाते हुए रेल–जल अंतर–मॉडल परिवहन को तेजी से विकसित किया। जनवरी से मई तक, राष्ट्रीय रेलवे रेल–जल अंतर–मॉडल परिवहन की मात्रा 75.8 लाख टीईयू तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 11.0 प्रतिशत अधिक है।शसिंगल बिल ऑफ लैडिंगश लॉजिस्टिक्स उत्पादों की कुल बुकिंग 47000 टीईयू रही, जिसे बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ऑटोमोबाइल परिवहन सेवाओं में और सुधार किए गए, जिससे सड़क और समुद्री परिवहन प्रभावी रूप से जुड़ गए। जनवरी से मई तक, चाइना रेलवे ने 824000 निर्यातित ऑटोमोबाइल का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इनमें 422000 नई ऊर्जा वाहन शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 110.3 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे चीनी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए एक त्वरित मार्ग मिला है।

रोहिताश्य राय बने झारखंड के नए महाधिवक्ता, राजीव रंजन का इस्तीफा मंजूर

रांची, (एजेंसी)। झारखंड सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितश्य रॉय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इसकी अधिसूचना रविवार देर शाम जारी की गई है। इसके पहले रविवार सुबह पिछले छह साल से महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे राजीव रंजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना इस्तीफा भेजा था। विधि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल ने महाधिवक्ता पद से राजीव रंजन द्वारा 14 जून को सौंपे गए त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितश्य रॉय को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है रोहितश्य रॉय झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से संवैधानिक, दीवानी तथा सेवा संबंधी मामलों की पैरवी करते रहे हैं। हाईकोर्ट में रिट याचिकाओं, सिविल विवादों, अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं से जुड़े मामलों में उनकी विशेष पहचान रही है। कानूनी क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सक्रिय अभ्यास को देखते हुए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत-स्लोवाकिया संबंध बने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप' का दर्जा देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार जताते हुए उन्हें भारत का सच्चा मित्र और अनुभवी नेता बताया। उन्होंने कहा कि फिको ने भारत–स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक पल साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ता विश्वास, साझा प्राथमिकताएं और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण इस नई साझेदारी का आधार हैं। उन्होंने भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया के सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि इसे जल्द लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप और व्यापारियों को अधिकतम लाभ मिल सके। तकनीक और डिजिटल सहयोग को भविष्य की साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए समझौते डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर 'इंडिया चेयर' स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत और स्लोवाकिया की साझा सोच है कि एआई मानवता की सेवा और प्रगति का माध्यम बने तथा उसका भविष्य केवल नवाचार ही नहीं, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानव गरिमा पर आधारित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में स्लोवाकिया का पहला उपग्रह भारत ने लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि आज भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है और स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रक्षा सहयोग पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दोनों देशों के गहरे विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आज 'लेटर ऑफ इंटेंट' पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद दोनों देशों की सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे वहां की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पूर्वोत्तर की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर रहा गुवाहाटी, दक्षिण–पूर्व एशिया से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला गुवाहाटी अब धीरे–धीरे भारत के दक्षिण–पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह शहर क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और विकास के लिहाज से लगातार रणनीतिक महत्व हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि गुवाहाटी में आने वाले दिनों में कई ऐतिहासिक विकास कार्यों की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में उन्होंने शहर और उसके आसपास चल रही तथा प्रस्तावित विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लिखा, "पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार अब भारत का दक्षिण–पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है। गुवाहाटी आने वाले दिनों में कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रहा है। इसी को देखते हुए मैंने राजधानी और उसके आसपास चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।" हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में किसी विशेष परियोजना का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह बयान ऐसे समय आया है जब असम में, विशेषकर गुवाहाटी में, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत गुवाहाटी को आर्थिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नापाक हरकतें बंद कर दे पाकिस्तान, नहीं तो अब दाना–पानी कर देंगे बंद – रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगरा की इस धरती पर वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके मुझे बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के कोने–कोने में जहां भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुझे आमंत्रित

किया जाता है, मैं बराबर हर कार्यक्रम में पहुंचता हूं। एक कार्यक्रम को भी मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और संघर्ष इतना बड़ा है कि देश उनको कभी भूल नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वह भारत की एक सोच के प्रतीक थे, जो किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान और मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते थे। अकबर ने तो महाराणा प्रताप से समझौता करने की कोशिश की। अगर महाराणा चाहते थे तो अकबर के साथ समझौता कर लेते और महलों में बहुत ही सुख एवं आनंद से अपनी जिंदगी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने महलों का कोमल बिस्तर छोड़कर पत्थरों पर सोना मंजूर किया। उन्होंने महलों का छप्पन भोग छोड़कर घास की रोटी खाकर भारत के स्वाभीमान की रक्षा की, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। रक्षा मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने हर कष्ट सहा, लेकिन कभी–कभी मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी की भूमि को दुश्मन के खून से लाल कर दिया था।

बदला हुआ गोरखपुर बनेगा देश के लिए विकास मॉडल – सीएम योगी

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर को विकास का बेहतरीन मॉडल बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में शहर ने बीमारी, बदहाल बुनियादी ढांचे, जलभराव, अपराध और पहचान के संकट से निकलकर विकास, सुशासन और आधुनिक सुविधाओं के नए युग में प्रवेश किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नई परियोजनाओं के जरिए गोरखपुर आने वाले समय में देश के लिए एक आदर्श शहरी विकास मॉडल बनकर उभरेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए की लागत से 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदला हुआ गोरखपुर, बदलते उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की नई पहचान का प्रतीक है।भारत पर्यटन गाइड सीएम योगी ने कहा कि आज गोरखपुर महानगर की लगभग एक हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। यह दिन प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि हम प्रदेश के सुपोषण मिशन के द्वितीय चरण का शुभारंभ भी कर रहे हैं। इस योजना का लाभ आने वाले समय में प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चों को मिलेगा। अगर बचपन सुरक्षित है, तो भविष्य भी सुरक्षित है। इस बचपन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। जब मां स्वस्थ होगी, तभी बच्चा स्वस्थ होगा। जो भी बच्चा पैदा होता है, उसके जीवन के प्रारंभिक हजार दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इन हजार दिनों में बच्चे की उचित देखभाल की जाए, तो न केवल उस परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक सशक्त नींव तैयार होती है।उन्ह्होंने कहा कि बच्चा केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि समाज का और अंततः पूरे राष्ट्र का भविष्य होता है।

दोनों देशों की साझेदारी नए अवसरों के द्वार खोल रही है - केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि जैसे–जैसे भारत 'विकसित भारत' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, फ्रांस के साथ उसकी साझेदारी सह–नवाचार (को–इनोवेशन) और तकनीकी प्रगति के नए अवसरों के द्वार खोल रही है। साथ ही यह ऐसी तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा दे रही है, जो केवल दोनों देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक साबित होंगी। उन्होंने फ्रांस के नीस शहर में एक "प्रोडक्टिव दिन" का समापन करते हुए नीस के मेयर एरिक सियोटी की मौजूदगी में सरकार, उद्योग, नवाचार और निवेश जगत के प्रमुख नेताओं के साथ एक रात्रिभोज का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "भारत–फ्रांस नवाचार वर्ष की पृष्ठभूमि में यह शाम विचारों के आदान–प्रदान और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा उभरते क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने का एक बेहतरीन मंच साबित हुई।" इस बीच सरकार ने कहा कि भारत का 'विकसित भारत 2047' का विजन और फ्रांस का 'फ्रांस 2030' मिशन भविष्य–केंद्रित नवाचार साझेदारी को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इससे नई और विघटनकारी तकनीकों में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से भारत और फ्रांस ने इंडिया–फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाने का फैसला किया है। यह रोडमैप दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के सह–विकास, भरोसेमंद तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ाने तथा लोगों, पर्यावरण और साझा समृद्धि के लिए ठोस परिणाम हासिल करने का मार्गदर्शन करेगा। भारत और फ्रांस नवाचार को आर्थिक मजबूती, सतत विकास, रणनीतिक स्वायत्तता और तकनीकी एवं औद्योगिक संप्रभुता का प्रमुख आधार मानते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों देशों का मानना है कि मजबूत नवाचार साझेदारी से उनकी पूरी नवाचार क्षमता का उपयोग हो सकेगा और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने में भी मदद मिलेगी।

'भारत इनोवेट्स 2026' भारत–फ्रांस की साझेदारी में अहम मील का पत्थर– धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि 'भारत इनोवेट्स 2026' भारत–फ्रांस की साझेदारी में एक मील का पत्थर है। साथ ही, कहा कि यह मानवता की भलाई के लिए युवा भारती इनोवेटर्स द्वारा बनाए जा रहे सॉल्यूशंस को वैश्विक मंच प्रदान करता है। 'भारत इनोवेट्स 2026' का उद्घाटन संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ओर से फ्रांस के नीस में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "फ्रांस के नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भारत–फ्रांस साझेदारी में एक अहम मील का पत्थर है।" उन्होंने आगे लिखा, "भारत इनोवेट्स को भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम और फ्रांस के तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेक्टर के बीच एक पुल के तौर पर देखने पर माननीय राष्ट्रपति का जोर, उभरती टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज और इनोवेशन के क्षेत्रों में हमारे सहयोग की

बढ़ती महत्वाकांक्षा और गहराई को दर्शाता है। वहीं, प्रधानमंत्री का कहना कि इनोवेशन की असली महानता सिर्फ उसके वैल्यूएशन में नहीं, बल्कि लोगों पर पड़ने वाले उसके असर में है। 'एआई फॉर ऑल' (सभी के लिए एआई) से लेकर 'टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी' (मानवता के लिए टेक्नोलॉजी) तक, भारत न सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पावरहाउस के तौर पर, बल्कि दुनिया के लिए समाधान देने वाले देश के तौर पर भी उभर रहा है।" प्रधान के मुताबिक, बड़े पैमाने, तेजी और टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, 'भारत इनोवेट्स' यह दिखाता है ।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगापुर रवाना

आंध्र प्रदेश, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू रविवार को सिंगापुर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। यह दौरा अमरावती और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए निवेश आकर्षित करने और सहयोग की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु से उड़ान भरी और रविवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, वे 15 और 16 जून को विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। सीएम नायडू सोमवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। वे मंगलवार को वर्ल्ड सिटीज समिट में भाग लेंगे और संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट्स के साथ राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और यूएन–हैबिटेट की कार्यकारी निदेशक अनाक्लाउडिया रॉसबाक के साथ लंच मीटिंग में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सिंगापुर के वरिष्ठ राज्य मंत्री लो येन लिंग से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद वे गूगल क्लाउड एशिया–पैसिफिक के अध्यक्ष करण बाजवा, जीआईसी की कार्यकारी समिति के सलाहकार लिम सियांग गुआन, वायसीएच ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष रॉबर्ट याप और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अध्यक्ष प्रोफेसर टैन इंग ची से मुलाकात करेंगे। वे सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से बातचीत करेंगे। साथ ही गृह मामलों के मंत्री के. षणमुगम और मानव संसाधन मंत्री डॉ. टैन सी लेंग से भी मुलाकात निर्धारित है। चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को काकतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सीबीएन/361 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वे एपीएसी सेमीकंडक्टर राउंडटेबल में भाग लेंगे और सुरबाना ज्यूरोंग–अमरावती प्लानिंग मीटिंग में शामिल होंगे।

नीट, पेपर लीक और बेरोजगारी पर छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, नीट पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के विभिन्न शहरों में जाकर छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। अभियान का पहला कार्यक्रम 17 जून को राजस्थान के कोटा शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसे देश का प्रमुख कोचिंग हब माना जाता है।हाल ही में विपक्षी गठबंधन की बैठक में नीट परीक्षा, पेपर लीक मामलों और युवाओं के सामने खड़ी रोजगार संबंधी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तक सीधे पहुंचने की रणनीति तैयार की है। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी समस्याएं, अनुभव और सुझाव खुलकर साझा कर सकें। साथ ही परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को भी मजबूत किया जाएगा।कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी का यह राष्ट्रीय छात्र संवाद अभियान 17 जून को कोटा से शुरू होगा। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज (इलाहाबाद), 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में भी बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र, युवा संगठन, शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ और विभिन्न परीक्षा घोटालों से प्रभावित अभ्यर्थी शामिल होंगे।कांग्रेस ने अभियान को व्यापक बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कैंपस विजिट, कोचिंग संस्थानों में संवाद, सोशल मीडिया अभियान, लाइव स्क्रीनिंग और इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए जाएंगे।

संपादकीय

स्थितियां और कठिन

पुलिस के निशाने पर वे कॉन्सर्ट्स हैं, जहां शराब की आड़ में ड्रग्स के सेवन का आरोप है। अब प्रशासन ने नो–अल्कोहल की शर्त लगा दी है, तो इन इवेंट्स की चमक भी चली गई है। तकरीबन डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्सर्ट इकॉनमी की चर्चा करते हुए संदेश दिया था कि भारत में लाइव म्यूजिक और अन्य इवेंट्स की अपार संभावनाएं हैं। उसके बाद इस वर्ष संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने इस क्षेत्र को विकास के एक उभरते इंजन के रूप में पेश किया। रिपोर्ट में इसे ऑरेंज इकॉनमी का हिस्सा बताया गया। इसका जिक्र किया गया कि 2024 में भारत का लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया। कोल्डप्ले, डुआ लिपा, लिनकिन पार्क, मरून–5 आदि जैसे बैंड्स और ए.पी. ढिल्लन, दलजीत दोसांज आदि जैसे कलाकारों के इवेंट्स में उमड़ रही भीड़ से इस उद्योग के और फूलने–फलने की आस जोड़ गई थी। लेकिन हालिया घटनाओं से इस कथित इंडस्ट्री की चमक फीकी पड़ गई है। इस कारोबार के गढ़ मुंबई में गुजरे अप्रैल में एक इवेंट के दौरान नशे के ओवरडोज से दो छात्रों की मौत की खबर ने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। उससे घटनाओं का जो सिलसिला चला, उस कारण कई तय इवेंट अचानक रद्द करने पड़े। इससे तय कार्यक्रमों को लेकर अनिश्चय का माहौल बन गया है। बताया जाता है कि आयोजकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय शोहरत के जिन कलाकारों के कार्यक्रम तय किए गए, उनको लेकर अनिश्चय घिरा हुआ है। पुलिस कार्रवाई के निशाने पर मुख्य रूप से वे आउटडोर इवेंट्स हैं, जिनके बारे में आरोप है कि शराब की आड़ में वहां मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। जानकारों का कहना है कि चूंकि अब प्रशासन ने नो–अल्कोहल की शर्त लगा दी है, तो इन इवेंट्स की चमक भी चली गई है। ये चेतावनी पहले ही दी गई थी कि भारत में बड़े पैमाने पर कॉन्सर्ट आयोजित करने के लिए पर्याप्त आधुनिक स्टेडियम या ऑडिटोरियम नहीं हैं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा मानकों पर अमल की चुनौती भी है। ये सब किए बिना कॉन्सर्ट इकॉनमी का गुणगान शुरू कर दिया गया। अब मुश्किलें सिर चढ़ कर बोल रही हैं। ईरान युद्ध से बढ़ी महंगाई ने स्थितियां और कठिन बना दी है।

खाद्य हानि से खाद्य नेतृत्व की ओर

चिराग पासवान

दक्षिण एशिया खाद्य प्रणालियों की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। समृद्ध कृषि–जैव विविधता वाला एक प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद, खेत से उपभोक्ता तक पहुँचने की प्रक्रिया में अभी तक बहुत अधिक मूल्य नष्ट हो जाता है जो किसानों, रोजगार और पोषण के लिए एक चूका हुआ अवसर है। भारत इस विरोधाभास का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत दूध और दालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक तथा फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं, भंडारण, लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण में मौजूद कमियों के कारण खाद्य पदार्थों की बड़ी मात्रा में हानि होती रहती है। इससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित वैश्विक विकास प्राथमिकताओं की दिशा में होने वाली प्रगति प्रभावित होती है। यह केवल अक्षमता भर नहीं है, बल्कि चूका हुआ अवसर भी है। बर्बाद होने वाले खाद्य पदार्थों का प्रत्येक टन, किसानों की खोई हुई आमदनी, युवाओं के लिए खोए हुए रोजगार के अवसर और परिवारों के लिए खोए हुए पोषण का प्रतीक है। इसलिए, इस हानि को मूल्य में बदलना अब एक क्षेत्रीय प्राथमिकता बन जाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण मूल्यवर्धित कृषि की संभावनाओं का पता लगाने की कुंजी है। यह खेतों को बाजारों से, किसानों को उद्योगों से तथा स्थानीय उत्पादन को क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ता है। इस प्रकार, यह कृषि और व्यापक आर्थिक परिवर्तन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। दशकों से कृषि नीतियों का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। इस प्रयास ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाएं हैं। लेकिन अब अगले चरण में मूल्य सृजन, रोजगार के अवसरों के सृजन, किसानों की आय में वृद्धि और पोषण संबंधी परिणाम बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत में, वर्तमान में कृषि उपज का केवल लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा ही प्रसंस्कृत किया जाता है। क्षेत्र की पूर्ण आर्थिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2030 तक लगभग 25 प्रतिशत करना आवश्यक है। साथ ही, कटाई के बाद होने वाली खाद्य हानियों को कम करना और प्रसंस्करण से जुड़े तंत्रों को मजबूत बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक मूल्य बना रहे। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की भंडारण अवधि बढ़ाता है, खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है तथा नए और घरेलू निर्यात बाजारों तक पहुँच के अवसर प्रदान करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आर्थिक मूल्य के बड़े हिस्से को उत्पादक देशों के भीतर ही बनाए रखने में मदद करता है, जिससे किसानों, उद्यमों और ग्रामीण समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। इस परिवर्तन को सफलतापूर्वक साकार करने के लिए मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण कृउत्पादन और संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने में समन्वित निवेश की आवश्यकता होगी। गुणवत्ता, सुरक्षा, ट्रेसबिलिटी तथा लागत–प्रभावशीलता के प्रति उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य होगा। दक्षिण एशिया की समृद्ध कृषि–जैव विविधता उच्च मूल्य वाले उत्पादों के विकास की अपार संभावनाएँ प्रदान करती है, विशेषकर ऐसे समय में जब वैश्विक मांग अधिक विविधतापूर्ण, पौष्टिक और विशिष्ट खाद्य उत्पादों की ओर बढ़ रही है। साथ ही, डिजिटल समाधान ट्रेसबिलिटी को मजबूत करने, गुणवत्ता मानकों में सुधार लाने और लगातार जटिल होते वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें सार्वजनिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसे निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक वातावरण को मजबूत बनाना, जोखिमों को कम करना तथा प्रभावी सार्वजनिक–निजी साझेदारी को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक होगा। भारत ने इस दिशा में पहले ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। ये कदम बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने, कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिससे अधिक गतिशील, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के लिए नींव रखी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण केवल आर्थिक दक्षता के बारे में ही नहीं हैकृयह आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। पूरे दक्षिण एशिया में लाखों युवा हर वर्ष श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, जबकि कृषि क्षेत्र अकेले अब इस बढ़ती हुई श्रम शक्ति को समाहित करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है।

अमेरिका व ईरान के बीच बने समझौते मसौदे के वैश्विक मायने

कमलेश

परमाणु प्रसार पर नियंत्रणरू ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने, यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने तथा परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में सहमति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल में उभरे समझौता–ढांचे (थ्तंउमूवता ।हतममउमदज) को यदि अंतिम रूप मिल जाता है, तो इसके प्रभाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक ऊर्जा बाजार और विश्व राजनीति पर पड़ेंगे। समझौते में युद्धविराम, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, तेल प्रतिबंधों में राहत, ईरान की जमी हुई संपत्तियों की रिहाई तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इसे 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक घटनाक्रमों में गिना जा सकता है। आइए इसके वैश्विक मायने को क्रमशः समझते है पहला, वैश्विक ऊर्जा बाजार को मिलेगी बड़ी राहतरू होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के तेल और स्छळ व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर रणनीति पूर्वक ईरान ने अपना मजबूत कब्जा जमा लिया है। लिहाजा, इसके खुलने और तनाव घटने से कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा। समझौते की खबर आते ही वैश्विक बाजारों में तेल कीमतों में गिरावट और शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। दूसरा, पश्चिम एशिया में घटेगा युद्ध का खतरारू यदि अमेरिका–ईरान टकराव कम होता है, तो लेबनान, इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव कम होने की संभावना बढ़ेगी। समझौते के तहत क्षेत्रीय संघर्षों को शांत करने की बात भी सामने आई है। इससे भारत को लाभ यह होगा कि यूरोप, अरब देशों, मध्य एशिया के देशों और रूस के साथ विकसित होने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक परिवहन कॉरिडोर के काम में गति आएगी। तीसरा, परमाणु प्रसार पर नियंत्रणरू ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने, यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने तथा परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में सहमति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। साथ ही, पाकिस्तान पर भी परमाणु हथियार हटाने का दबाव बढ़ेगा। चौथा, चीन और रूस की रणनीति पर असररू पिछले वर्षों में ईरान, चीन और रूस के बीच रणनीतिक निकटता बढ़ी थी। इससे भारत की भी परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि ईरान–पाकिस्तान–अफगानिस्तान के आतंकवादी कॉरिडोर को नियंत्रित करने में अमेरिका–चीन के षड्यंत्रकारी बाधक बन रहे थे।

रूस भी मजबूरी में ईरान को साथ दे रहा है। ऐसे में यदि अमेरिका–ईरान संबंध सुधरते हैं, तो तेहरान को पश्चिमी निवेश और बाजारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे उसकी चीन और रूस के अलावा पाकिस्तान पर रणनीतिक निर्भरता कुछ कम हो सकती है। यह वैश्विक शक्ति–संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। तेल आयात व अन्य सामान के सस्ता होने की संभावना बढ़ेगी। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा बेहतर होगी। चाबहार बंदरगाह और भारत–ईरान व्यापार को नई गति मिल सकती है। पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। यहां चीनी हस्तक्षेप कम होने से भारत पश्चिमी मोर्चे पर मजबूत होगा। छठा, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैंरू चूंकि समझौते पर अभी भी पूर्ण सहमति नहीं बनी है, क्योंकि चीन–रूस दिल से ऐसा नहीं चाहते। लिहाजा, ईरान के कट्टरपंथी गुट इसका विरोध कर रहे हैं और इजराइल–हिज्बुल्लाह मोर्चे पर तनाव भी बना हुआ है। चूंकि कट्टरपंथियों ने बलिदान देकर ईरान को इतना मजबूत बनाया है। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी ईरानी सरकार नहीं जा सकती। यही वजह है कि कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अंतिम हस्ताक्षर और कार्यान्वयन अभी अनिश्चित हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इसे 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक घटनाक्रमों में गिना जा सकता है। इससे तेल बाजार स्थिर होंगे, परमाणु संकट टलेगा, पश्चिम एशिया में शांति की संभावना बढ़ेगी और भारत सहित अनेक देशों को आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन इसकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और क्षेत्रीय शक्तियां अपने–अपने वादों का कितना पालन करती हैं। मेरी राय में यह समझौता जितनी जल्दी हो जाए, भारतीय हित उतनी जल्दी ही सधने शुरू जाएंगे।

पीओके की जनता को पाकिस्तानी जुल्मों से निजात दिलाने के लिए भारत को सीधे दखल देना चाहिए

नीरज

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब हालात सिर्फ बिगड़ नहीं रहे हैं बल्कि यह इस्लामाबाद के खिलाफ खुले जनविद्रोह का रूप ले चुके हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान दशकों से अपने कब्जे का हिस्सा बताकर दुनिया के सामने कश्मीर का झूठा राग अलापता रहा, वही लोग आज सड़कों पर उतरकर उसके दमनकारी चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। आटे पर सब्सिडी, बिजली दरों में कमी, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों जैसी बुनियादी मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब पाकिस्तान की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ व्यापक जनआक्रोश में बदल चुका है। जम्मू–कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पुलिस ने जिस बर्बरता का प्रदर्शन किया है, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और इंटरनेट सेवाएं बंद कर पूरे क्षेत्र को अंधेरे में धकेल दिया गया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अब तक दर्जनों नागरिक मारे जा चुके हैं और हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली, भीमबर और पुंछ जैसे क्षेत्रों में हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों की जमीनों को डुबोकर मंगला बांध बनाया गया, उन्हीं लोगों को आज आसमान छूते बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने वाला यह विशाल बांध स्थानीय जनता के लिए अभिशाप बन चुका है। हजारों परिवार उजड़ गए, लेकिन पुनर्वास तक नहीं मिला। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान करता है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिलता। यही कारण है कि यह आंदोलन अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई बन गया है। पाकिस्तान ने तथाकथित विधानसभा और संविधान का ढांचा तो खड़ा किया, लेकिन असली सत्ता हमेशा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हाथों में रही। वहां की विधानसभा महज कठपुतली संस्था बनकर रह गई है। हाल ही में आरक्षित सीटों को लेकर आए फैसले ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। इन सीटों के जरिये पाकिस्तान अपनी पसंद की सरकारें थोपता है और कश्मीरी आवाजों को कुचल देता है। यही कारण है कि लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान उन्हें नागरिक नहीं, गुलाम समझता है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि पाकिस्तान ने संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके नेताओं के सिर पर इनाम घोषित किए गए हैं। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मीडिया पर सेंसरशिप थोप दी गई है और इंटरनेट बंद कर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दमन जितना बढ़ रहा है, जनाक्रोश उतना ही उग्र हो रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका में बसे कश्मीरी प्रवासियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यह वही प्रवासी समुदाय है जिसे पाकिस्तान वर्षों तक भारत विरोधी प्रचार के लिए इस्तेमाल करता रहा। मगर अब वही लोग इस्लामाबाद के दमन के खिलाफ दुनिया को सच बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पीओके के लोगों के साथ जो बर्बरता की है उसके खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। बाइट। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। यह संकट उसे सीधे 1971 की याद दिला रहा है, जब दमन और सैन्य बल के सहारे पूर्वी पाकिस्तान को दबाने की कोशिश ने अंततः बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता खोला था। आज पीओके में भी वही हालात दिखाई दे रहे हैं। जनता का भरोसा टूट चुका है और पाकिस्तान केवल बंदूक के दम पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भय के सहारे किसी क्षेत्र को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। उधर, भारत के लिए यह स्थिति सामरिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जमीनी हकीकत यह है कि वैसे तो पूरा जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है लेकिन पीओके में पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। अब जब वहां की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और भारत के साथ मिलने की बातें मुखर होने लगी हैं तो सवाल उठता है कि भारत को क्या पीओके में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए? इस सवाल पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि सीधे हस्तक्षेप की बजाय भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों को और आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए। उनका कहना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों के सामने यह प्रश्न मजबूती से रखना होगा कि आखिर पाकिस्तान किस नैतिक आधार पर कश्मीर की बात करता है, जब उसके कब्जे वाले क्षेत्र में जनता को जीने तक का अधिकार नहीं है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यदि भारत ने पीओके में सीधे हस्तक्षेप किया तो यह सीधे सैन्य दखल के रूप में देखा जायेगा और यह दो परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद और उकसावे की नीति अपनाता रहा है इसलिए वह किसी भी प्रत्यक्ष कार्रवाई को युद्ध का बहाना बना सकता है। इसलिए भारत को अत्यंत संतुलित लेकिन दृढ़ रणनीति अपनानी होगी। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के पास कई विकल्प हैं। जैसे पीओके की जनता के साथ मानवीय और सामाजिक संपर्क बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरना, सीमा पर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाना क्योंकि पाकिस्तान ध्यान भटकाने के लिए आतंकवादी घुसपैठ बढ़ा सकता है। साथ ही पीओके के लोगों के लिए राजनीतिक संदेश देना होगा कि भारत उन्हें अपना नागरिक मानता है और उनके अधिकारों के साथ खड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि जम्मू–कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए आरक्षित 24 सीटों को सक्रिय राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल, फिलहाल भारत के लिए सबसे प्रभावी रास्ता यही है कि वह धैर्य, कूटनीति और रणनीतिक दबाव का संयोजन अपनाए। पीओके में जो आग भड़की है, वह केवल आर्थिक संकट का परिणाम नहीं, बल्कि दशकों के दमन, शोषण और राजनीतिक अपमान का विस्फोट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब उसका झूठ उसके अपने कब्जे वाले क्षेत्र में ही टूट रहा है। जिस जमीन को वह कश्मीर की आजादी का प्रतीक बताता था, वहीं की जनता आज उसके खिलाफ आजादी की आवाज बुलंद कर रही है। हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में पीओके का भारत के साथ स्वाभाविक जुड़ाव और तेज हो सकता है। स्थानीय जनता जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आरपार की लड़ाई के मूड़ में दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि इस्लामाबाद के लिए अब केवल बंदूक और दमन के सहारे वहां अपनी पकड़ बनाए रखना आसान नहीं रहेगा। स्थानीय जनता के भीतर पाकिस्तान विरोधी भावना लगातार गहरी हो रही है। यदि पाकिस्तान ने अपनी दमनकारी नीतियां नहीं बदलीं, तो वह दिन दूर नहीं जब पीओके की जनता खुद पाकिस्तान के कब्जे को खुली चुनौती देते हुए भारत के साथ खड़े होने का रास्ता चुन सकती है।

भारत की समुद्री रणनीति का प्रमुख केंद्र

कौटिल्य की यह सीख सदियों पहले ही शासन और रणनीति की मूल सोच का हिस्सा बन चुकी थी, और आज के समय में यह पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक होकर सामने आई है। आज देशों की परीक्षा केवल उनकी अर्थव्यवस्था के आकार या सैन्य ताकत से नहीं हो रही, बल्कि इस बात से हो रही है कि वे भूगोल को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, भविष्य का कितना सही अनुमान लगाते हैं और अवसर के खतरे में बदलने से पहले कितनी तेजी से निर्णय लेते हैं। ग्रेट निकोबार भारत के लिए ऐसी ही एक बड़ी परीक्षा है। यह भारतीय मानचित्र के दक्षिणी–पूर्वी छोर पर स्थित एक दूरस्थ द्वीप जैसा प्रतीत होता है। ऐसी जगह जिसे दशकों से लगभग अछूता छोड़ दिया गया है और जिसे वैसे ही रहने देना चाहिए। परंतु ग्रेट निकोबार भारत की अग्रिम समुद्री चौकी है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के समीप स्थित यह द्वीप दुनिया की ओर भारत की सबसे अहम सामरिक अवसर में से एक है। अतरू ग्रेट निकोबार के प्रस्तावित विकास को केवल एक अवसंरचना परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह केवल एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, टाउनशिप या बिजली संयंत्र बनाने का प्रश्न नहीं है। यह वास्तव में इस बात की सामरिक परीक्षा है कि क्या भारत अपनी इस दुर्लभ भौगोलिक बढ़त को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने के लिए तैयार है। सदियों से हिंद महासागर ने भारत की नियति को आकार दिया है। इसी समुद्री क्षेत्र ने हमारे व्यापार, हमारे विचारों और हमारे सभ्यतागत प्रभाव को विश्व भर में पहुंचाया, परन्तु कई बार यही हमारी कमजोरियों का कारण भी बना। तथापि, स्वतंत्रता के पश्चात् लंबे समय तक भारत की सामरिक सोच मुख्य रूप से स्थल–आधारित रही। यह निर्विवाद है कि ग्रेट निकोबार अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है। यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है। प्रस्तावित परियोजना का कुल क्षेत्रफल 166.10 वर्ग किलोमीटर है, जो सम्पूर्ण द्वीपसमूह के कुल क्षेत्रफल का केवल लगभग 2 प्रतिशत है। इसमें से 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को परियोजना के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है, जो द्वीप समूह के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1.82 प्रतिशत है। यह दक्षिण–पूर्व एशिया के निकट स्थित है तथा मलक्का स्ट्रेट, 60 चौनल, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट जैसे प्रमुख वैश्विक समुद्री मार्गों के समीप आता है। वास्तविक सामरिक दृष्टि से देखें तो यह भारत की पूर्वी समुद्री चौकी है। इसका महत्व तब और स्पष्ट हो जाता है जब इसे केवल भूभाग के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि महासागरीय रणनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। कल्पना कीजिए उन जहाजों की, जो अदन की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्जा से भरे मालवाहक जहाज, जो पश्चिम एशिया और अफ्रीका से पूर्वी एशिया की ओर जा रहे हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला कंटेनर यातायात तथा नौसैनिक संसाधन, निगरानी मंच और लॉजिस्टिक श्रृंखलाएँ, जो इन जलमार्गों से होकर गुजर रही हैं। हिंद महासागर अब शांत समुद्र नहीं रहा। यह तेजी से एक भीड़भाड़ वाले सामरिक क्षेत्र में बदल रहा है। ऊर्जा आपूर्ति, कंटेनर यातायात, नौसैनिक तैनाती, द्वीपीय सुविधाएं, समुद्र के नीचे बिछी केबलें और समुद्री निगरानी अब एक बड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुकी हैं। यह शायद मुख्य भूमि पर बैठे कई लोगों को दिखाई न दे, परन्तु देशों के भविष्य के लिए यह बेहद निर्णायक है। हाल की एक महत्वपूर्ण प्रगति यह है कि अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ने वाली दशकों पुरानी कैनल परियोजना को स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब लगभग 90 किलोमीटर लंबे मल्टी–मोडल लैंड ब्रिज की योजना अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह परियोजना टेंथ पैरेलल के साथ दो नव–डिजाइन किए गए गहरे समुद्री बंदरगाहों को जोड़ेगी कृ एक अंडमान सागर के किनारे रणोंग में और दूसरा थाईलैंड की खाड़ी के किनारे चुम्फोन में। इसके साथ दोहरी ट्रैक्स वाली उच्च गति रेल, बहु–लेन सड़क, तेल एवं गैस के लिए ऊर्जा पाइपलाइनें तथा वायु एवं डिजिटल ग्रिड भी प्रस्तावित हैं। ये सभी कारक मिलकर इंडो–पैसिफिक व्यापार मार्गों को पूरी तरह पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और आर्थिक शक्ति का केंद्र सीधे अंडमान बेसिन की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। मलक्का स्ट्रेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक चोकपॉइंट्स में से एक है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और अत्यंत मूल्यवान ऊर्जा संसाधनों (तेल और एलएनजी) तथा वैश्विक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ग्रेट निकोबार की गलाथिया खाड़ी 60 चौनल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जो मलक्का स्ट्रेट को अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों से जोड़ती है। अनुमान है कि हर साल लगभग एक लाख जहाज मलक्का स्ट्रेट 60 चौनल मार्ग से गुजरते हैं। मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जैसे सामरिक चोकपॉइंट्स के निकट स्थित होने के कारण यह द्वीप भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त प्रदान करता है। कोई भी गंभीर सामुद्रिक शक्ति ऐसे भौगोलिक तथ्यों की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। हिंद महासागर क्षेत्र (ढ्ढह्रक्र) में अनेक शक्तिशाली देश बंदरगाहों, लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं, समुद्री पहुँच सुविधाओं, नौसैनिक संसाधनों, निगरानी प्रणालियों और आर्थिक गलियारों के माध्यम से निरंतर अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। भारत का उत्तर संकोचपूर्ण नहीं हो सकता। उसका उत्तर सामरिक सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। संप्रभुता केवल मानचित्र पर सीमाएँ खींच देने से सुदृढ़ नहीं होती। वह तब सशक्त होती है जब कोई भूभाग जुड़ा हुआ, आबाद, सुविधायुक्त, उत्पादक और सामरिक रूप से उपयोगी बनता है। अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और विद्युत संयंत्र अलग–अलग परियोजनाएँ नहीं हैं। ये सभी मिलकर उस पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से भारत एक निर्णायक सामुद्रिक स्थान पर विश्वसनीय, सतत और बहुआयामी उपस्थिति बनाए रख सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समुचित जांच–पड़ताल और आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह स्वीकार किया कि यह परियोजना केवल द्वीप और उसके आसपास के सामरिक क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंगापुर केवल इसलिए एक महान सामुद्रिक केंद्र नहीं बना क्योंकि उसका भौगोलिक स्थान अनुकूल था। उसने उस स्थान के आस–पास आवश्यक क्षमताओं का निर्माण किया। भौगोलिक स्थिति ने उसे अवसर दिया, और उसके अवसंरचनात्मक विकास ने उस अवसर को प्रभाव में परिवर्तित किया। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया एक और महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि कोई दूरस्थ द्वीप भी, यदि उसे लॉजिस्टिक और परिचालन अवसंरचना से सुसज्जित किया जाए, तो असाधारण सामरिक महत्व प्राप्त कर सकता है। सामुद्रिक शक्ति केवल भूगोल से नहीं बनतीय वह भूगोल का उपयोग करने की आवश्यक क्षमता विकसित करने से निर्मित होती है।ग्रेट निकोबार भारत को यह सब एक संतुलित और विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण के साथ करने का अवसर प्रदान करता है। यह व्यापार को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है, विदेशी ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर निर्भरता कम कर सकता है, साथ ही भारत की सामुद्रिक पहुँच को विस्तारित कर सकता है तथा दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार और व्यापक इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक सामरिक मंच के रूप में कार्य कर सकता है। ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत के उस सामग्री पर निर्भरता को कम कर सकता है जिसे वर्तमान में विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से ट्रांसशिप किया जाता है। इससे सप्लाई चेन सुदृढ होगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और भारत को अपने सामग्री की आवाजाही पर अधिक नियंत्रण और निश्चितता प्राप्त होगी। निस्संदेह, ग्रेट निकोबार पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इस स्तर की किसी भी परियोजना को पारिस्थितिक सावधानी, कानूनी अनुपालन, वैज्ञानिक निगरानी और वास्तविक शमन उपायों के साथ लागू किया जाना चाहिए। विकास लापरवाह नहीं हो सकता। लेकिन पर्यावरणीय संवेदनशीलता को सामरिक चिंतन पर स्थायी वीटो का आधार भी नहीं बनाया जा सकता। वास्तविक चुनौती पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच चयन करने की नहीं है। वास्तविक चुनौती यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ाया जाए। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या भारत इस सामरिक द्वीप का उत्तरदायित्व पूर्वक विकास करना चाहता है, अथवा फिर ऐसे समय में जब पूरा इंडो–पैसिफिक क्षेत्र पुनर्गठित हो रहा है, वह इस द्वीप को अविकसित और अपर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ छोड़ देगा। भारत एक कॉन्टिनेंटल और सामुद्रिक कृ दोनों प्रकार की शक्ति है।

हत्यारोपी पति सास व पड़ोसन को आजीवन कारावास, मोटरसाइकिल की मांग को लेकर किया प्रताड़ित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के तीन आरोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार आजमगढ़ निवासी अब्दुल रईस ने खेतासराय में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन अंजुम का निकाह मवई गांव के इमरान के साथ 31 दिसंबर 2017 को हुआ था। उपहार में काफी सामान दिया गया था किंतु मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति इमरान सास रेहाना तथा ननद मल्लिका व साबिरा तथा पड़ोस की चुन्नी पत्नी सिराज उसे मारती पीटती थी। 13 मई 2018 को दिन में 3रू00 बजे यह लोग अंजुम को मार पीटकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने पति इमरान सास रेहाना को दहेज हत्या में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 25–25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया जबकि पड़ोसन चुन्नी को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया।

?लखनऊ में लिबर्टी का 427वां मेगा एक्सक्लूसिव शोरूम शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। देश की अग्रणी फुटवियर निर्माता कंपनी लिबर्टी शूज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने 427वें मेगा एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ कर उपभोक्ताओं को आधुनिक खरीदारी अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। हजरतगंज में स्थापित इस नए मेगा शोरूम का उद्घाटन भव्य समारोह के बीच किया गया। कंपनी का उद्देश्य देश के प्रमुख महानगरों में ऐसे मेगा शोरूम स्थापित करना है, जहां ग्राहकों को लिबर्टी के सभी प्रमुख ब्रांड और नवीनतम उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकें। उद्घाटन अवसर पर लिबर्टी ग्रुप के मुख्य परिचालन अधिकारी रमन बंसल ने कहा कि लखनऊ न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बल्कि देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के उपभोक्ताओं ने हमेशा लिबर्टी ब्रांड पर भरोसा जताया है और यही विश्वास कंपनी को यहां अपने विस्तार के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि शहर में एक और एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन कंपनी के लिए विशेष महत्व रखता है।रमन बंसल ने कहा कि लिबर्टी भारतीय फुटवियर उद्योग की अग्रणी कंपनियों में शामिल है और दशकों से अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि कंपनी को एक स्वदेशी भारतीय ब्रांड होने पर गर्व है। लिबर्टी की उत्पादन इकाइयां करनाल, घरौंडा, लिबर्टीपुरम, देहरादून, पांवटा साहिब और रुड़की में स्थित हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रतिदिन 50 हजार से अधिक जोड़ी जूतों का निर्माण किया जाता है। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता, नवाचार और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार करना कंपनी की प्राथमिकता है।

मेडिकल कॉलेज जौनपुर में जटिल ऑपरेशन सफल, चिकित्सकों ने बचाई मरीज की जान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के चिकित्सकों ने एक जटिल शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 24 वर्षीय युवक को नया जीवन दिया है। शाहगंज निवासी युवक को पेशाब में तेज जलन, रुक–रुक कर मूत्र आने तथा असहनीय दर्द की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि मरीज के मूत्राशय और मूत्रमार्ग में पथरी फंसी हुई है, जिससे उसकी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। मरीज की हालत को देखते हुए तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। सर्जरी विभागाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. (डॉ.) ए.ए. जाफरी के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने आधुनिक तकनीक की मदद से इमरजेंसी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान यूआरएसएल और डीजे स्टेंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए मूत्रमार्ग और मूत्राशय में फंसी लगभग 15 मिमी की कठोर पथरी को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को तत्काल राहत मिली और उसकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। इस सफलता में डॉ. हिमांशु सिंह, डॉ. राजन्य प्रजापति तथा नर्सिंग एवं सहायक स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं एनेस्थीसिया देने में डॉ. आदर्श यादव का विशेष योगदान रहा। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) आर.बी. कमल ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान का लक्ष्य मरीजों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह सफलता मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ चिकित्सा क्षमता और टीम भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है।

रास्ते में मिट्केटी डालने के विवाद में वृद्ध की हत्या, पांच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज चार आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में केराकत कोतवाली क्षेत्र के धरौरा गांव में रास्ते में मिट्टी डालने के विवाद को लेकर हुए संघर्ष में एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पांच लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अंतर्गत धरौरा गांव निवासी रामदुलार सरोज (68) सोमवार को अपने घर पर थे। परिजनों का आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर पट्टीदारों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामदुलार को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र लोहा सरोज ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि सतीश, शुभम, अमरेश, किशन सहित अन्य लोगों ने उनके पिता पर हमला किया। उन्होंने बताया कि परिवार द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि विपक्षी पक्ष अधिक रास्ते की मांग कर रहा था और निर्माण कार्य का विरोध कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर पांच लोगों के विरुद्ध हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।इस संबंध में मंगलवार को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि केराकत थाना क्षेत्र में दो पट्टीदार पक्षों के बीच जमीन में मिट्टी डालने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद एवं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नेपाल में अंतरराष्ट्रीय ज्ञान गौरव सम्मान से सम्मानित हुए प्रो. अजय कुमार दुबे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर के टीडी कॉलेज में शिक्षक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे को नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ष्अंतरराष्ट्रीय ज्ञान गौरव सम्मानष से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें अध्यापन कार्य के प्रति निष्ठा, शैक्षिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के सफल निर्वहन तथा शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। नेपाल स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में 15 और 16 जून 2026 को षशिक्षा, साहित्य, समाज और संस्कृति का वैश्विक विमर्श रू चुनौतियां, अवसर एवं संभावनाएंष विषय पर आयोजित द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। नेवढ़िया क्षेत्र के रिकेबीपुर गांव निवासी प्रो. दुबे की शिक्षा टीडी कॉलेज जौनपुर से ही हुई है। वर्ष 1997 में एम.एड. अध्ययनरत रहते हुए उन्होंने यूजीसी द्वारा आयोजित नेट (जेआरएफ) परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्ष 1998 से वह टीडी कॉलेज के शिक्षक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कार्य परिषद सदस्य, शिक्षा संकाय के डीन, विद्या परिषद सदस्य, अध्ययन परिषद सदस्य, परीक्षा समिति सदस्य तथा प्रवेश समिति सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में वह महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'मंथन' के मुख्य संपादक हैं। प्रो. दुबे के सैकड़ों शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित चुके हैं। उन्होंने 12 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया है तथा देश–विदेश में आयोजित शैक्षिक संगोष्ठियों में व्याख्यान दिए हैं। उनके निर्देशन में शिक्षा संकाय के 16 शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में वह रोवर्स–रेंजर्स के जिला कमिश्नर का दायित्व भी निभा रहे हैं। इसके अलावा वे विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तथा पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख और प्रांत उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। उनके इस सम्मान से जनपद के शिक्षाविदों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है।

खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी में उत्तर प्रदेश बना देश का अग्रणी राज्य

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कृषि, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश ने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विशाल कृषि आधार, किसानों की मेहनत, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और बेहतर औद्योगिक वातावरण के बल पर उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है।प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई इस नीति ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नई गति प्रदान की है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न जनपदों में नई इकाइयों की स्थापना हो रही है और कई जिले खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं।खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश देश में सर्वाधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों वाला राज्य बन चुका है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों को मिलाकर राज्य में लगभग साढ़े तीन लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां संचालित हैं। देश के कुल खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में उत्तर प्रदेश की लगभग 14 से 15 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य की मजबूत औद्योगिक क्षमता और निवेश आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाती है।प्रदेश की सफलता के पीछे उसकी मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी शक्ति है। उत्तर प्रदेश देश में दूध, गन्ना, आलू तथा कई प्रमुख कृषि उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। कृषि उत्पादों की भरपूर उपलब्धता के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जिससे निवेशकों और उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।उद्यानिकी क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2025–26 के अनुमानित आंकड़ें के अनुसार प्रदेश कुल उद्यानिकी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य का कुल उद्यानिकी उत्पादन लगभग 536 लाख टन आंका गया है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 14.19 प्रतिशत है।

भारतीयों की मौत पर प्रधानमंत्री की चुप्पी चिंताजनक : संजय सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संजय सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर सरकार कमजोर रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की मौत और भारतीय जहाजों पर हुए ।

नाबालिग को बहकाकर घर से जेवर और नकदी चोरी कराने वाले गिरोह का भंडाफोड

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र में नाबालिग बालक को अपने प्रभाव में लेकर उसके घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चिनहट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना में शामिल दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने–चांदी के आभूषण, एक मोबाइल फोन तथा एक लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। मामले में बरामदगी के आधार पर मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।

संक्षिप्त खबरें

संकट के समय घबराएं नहीं, सूझबूझ से मनचलों को दें मात

लखनऊ, (संवाददाता)। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए महिलाओं का मानसिक रूप से मजबूत और अपने आस–पास के माहौल को लेकर सजग होना बेहद जरूरी है। अगर कभी किसी संकट में फंस जाएं तो घबराने की जगह मनचलों को अपनी सूझबूझ से मात दें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। आपका डर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में डरने की जगह लड़ना सीखें। ये बातें रविवार को आईआईएम मार्ग स्थित शालीमार गार्डन बे में मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस रुचिता चौधरी ने कहीं। मौका था अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अपराजिता कार्यक्रम का। सिचुएशनल अवेयरनेस पर आधारित इस कार्यक्रम में वीमेन पावर लाइन 1090 की पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचिता और विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट अमिता जैन ने सुरक्षा के गुर सिखाए। उद्यमी रिमझिम चौहान, शिक्षक सिमरन कौर और डॉ. अंकिता कुमारी ने भी जागरूक किया। कार्यक्रम आरडब्ल्यूए के सहयोग से किया गया। इस दौरान आरडब्ल्यूए के सभी सदस्य मौजूद रहे। खाए सुरक्षा के गुर अगर कभी भी आपको किसी व्यक्ति या सुनसान रास्ते पर कुछ अजीब या असुरक्षित महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज न करें। तुरंत वहां से हट जाएं या मदद लें। चलते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यह आदत आपको अपने परिवेश से काट देती है और अपराधियों को मौका देती है। नई जगह, सुनसान सड़क या रात के वक्त बाहर हों तो हर कुछ मीटर पर रुककर या सामान्य रूप से पीछे मुड़कर देखें। जब भी किसी अनजान जगह, बेसमेंट पार्किंग, या बंद हॉल में जाएं, तो पहले वहां से बाहर निकलने के रास्ता तलाश लें।

बच्चों को दिया गीता का ज्ञान

लखनऊ, (संवाददाता)। आशियाना के सेक्टर के स्थित अटल सेवा केंद्र में रविवार को अटल ज्ञानशाला का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन से एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र नाथ गुप्ता ने बच्चों को अच्छे और बुरे कर्म का मतलब समझाया। कहा कि गीता का मूल मंत्र निष्काम कर्म है। गीता के उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहने चाहिए। आशियाना रेजीडेंट्स एसोसिएशन की ओर से यह ज्ञानशाला आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर जनार्दन सिंह, एसएन गुप्ता, अतुल कुमार टंडन, गिरीश मेहरोत्रा, एमएल आहूजा, एसएस प्रसाद, एचसी सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे।

प्रवेश के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है। अभी तक फिलहाल तिथि बढ़ाने के संबंध में कोई जानकारी विवि की ओर से जारी नहीं की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थी सोमवार तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के अलावा शहर के अन्य महाविद्यालयों में भी आवेदन हो रहे हैं। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मई थी जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया था।

राम मंदिर के चढ़ावे में गबन की जांच के लिए पीएमओ से पहुंचे अफसर

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र भी सक्रिय हो गया है। रविवार को पीएमओ की तरफ से एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है। अफसर अपने स्तर से जांच पड़ताल के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) सोमवार को अयोध्या पहुंचेगी। टीम ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेने के साथ मंदिर के कर्मचारियों और चिह्नित संदिग्धों से पूछताछ करेगी। ट्रस्ट की ओर से की गई अब तक की जांच का पूरा ब्योरा भी जुटाएगी। इस बीच एक सप्ताह पहले उजागर हुए इस मामले में गबन के साक्ष्य मिलने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। मंदिर की दान राशि में हेरफेर का मामला बीते सप्ताह उजागर हुआ था। ट्रस्ट के पदाधिकारी तब से खुद ही गोपनीय जांच में जुटे हैं। ट्रस्ट के ऑफिस के पास किसी भी बाहरी शख्स के जाने पर रोक है। इन सबके बीच शनिवार को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ किरन एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। चर्चा थी कि एसआईटी रविवार से जांच शुरू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी सोमवार को अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू करेगी। टीम केवल धन के लेन–देन और तकनीकी पहलुओं की जांच ही नहीं, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि किसी स्तर पर संरक्षण, लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। किसी ट्रस्टी या पदाधिकारी की संलिप्तता या प्रशासनिक चूक के प्रमाण मिलने पर उनके अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराने का एलान करने वाले पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता विनय कटियार रविवार को अधिकारियों से मिले बिना ही लखनऊ रवाना हो गए। विनय कटियार ने शनिवार को अयोध्या पहुंचने के दौरान कहा था कि वह रविवार सुबह डीआईजी और एसएसपी से मिलकर राम मंदिर के चढ़ावे में कथित घपला करने वालों के खिलाफ शिकायत करेंगे तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि किसी ने श्रद्धालुओं के दान में गड़बड़ी की है तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए। हालांकि रविवार को उनके अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम नहीं हो सका और वह बिना किसी औपचारिक शिकायत के ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने रविवार को श्रीराम जन्मभूमि परिसर में दानपेटियों और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने चढ़ावा संग्रह, सुरक्षा और बैंक में जमा कराने तक की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने रामलला के गर्भगृह में रखी दान पेटियां भी देखीं।

भाजपा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को बर्बाद किया

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने देश में नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की और विरोधी दलों के नेताओं की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि यदि मीडिया निष्पक्षता से खबरें प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है।रविवार को आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ–साथ आगरा की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 में आगरा में 2090 प्राथमिक विद्यालय थे, जो अब घटकर 1633 रह गए हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में आगरा में 14 एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित थे, जबकि वर्तमान में केवल चार केंद्र ही कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी कम हुई है और सरकार सरकारी संस्थाओं को बंद कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ अत्याचार और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और समाज के कमजोर वर्गों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान शुरू की गई डायल–100 सेवा आम जनता के लिए उपयोगी साबित हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई स्थानों पर गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों के साथ अन्याय हुआ है तथा प्रशासनिक कार्यवाहियों में भेदभाव देखने को मिला है।पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से परेशान है, लेकिन सरकार इनके समाधान के बजाय ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही हैसमाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव समय पर कराने में भी सफल नहीं रही है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।

विभूतिखंड में सक्रिय अंतरजनपदीय नकबजनी गिरोह का भंडाफोड

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के पॉश इलाके विभूतिखंड में बंद मकानों, दुकानों और निर्माणाधीन भवनों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय नकबजनी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी की सर्विलांस टीम और थाना विभूतिखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो शातिर वांछित नकबजन गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से चोरी के 4 लाख 50 हजार रुपये नकद तथा सोने–चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।पुलिस के अनुसार थाना विभूतिखंड क्षेत्र में बीते कई सप्ताह से बंद मकानों और दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। इन घटनाओं के संबंध में थाना विभूतिखंड पर अलग–अलग तिथियों में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। 6 मई 2026 को दर्ज मुकदमा संख्या 152ध्2026, 11 मई 2026 को मुकदमा संख्या 157ध्2026 तथा 11 जून 2026 को मुकदमा संख्या 195ध्2026 अज्ञात चोरों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल था।घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने गिरोह तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया। जांच के दौरान 12 जून को गिरोह के एक सदस्य सत्तार खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से चोरी के 1 लाख 50 हजार रुपये बरामद हुए थे। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।इसी क्रम में रविवार को पुलिस उपायुक्त पूर्वी की सर्विलांस टीम और विभूतिखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मैक्स अस्पताल गेट नंबर–3 के सामने स्थित क्रॉसिंग के पास से दो अन्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कामिल पुत्र अमजद निवासी ग्राम अकरौली, थाना बनियाठेर, जनपद संभल तथा हीरालाल वर्मा पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम बैरीखेड़ा, थाना बनियाठेर, जनपद संभल के रूप में हुई है।

केजीएमयू में करंट लगने से पंप ऑपरेटर की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) परिसर में कार्यरत एक कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिसर में शोक का माहौल व्याप्त हो गया, जबकि कुछ कर्मचारियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्रामा सेंटर परिसर में प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राहुल गौतम पुत्र रमेश गौतम निवासी ग्राम लीलाखेड़ा, थाना दुबग्गा, जनपद लखनऊ के रूप में हुई है। राहुल गौतम की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह केजीएमयू में गोविंद फायर सर्विसेज के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ड्यूटी के दौरान राहुल गौतम विद्युत करंट की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए केजीएमयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। हालांकि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों की और स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।घटना के बाद मृतक के कुछ साथी कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी लापरवाही का आरोप लगाते हुए केजीएमयू ट्रामा सेंटर परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना था कि यदि सुरक्षा मानकों का समुचित पालन किया गया ।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता रैली एवं संगोष्ठी का हुआ आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकारों के प्रति जन–जागरूकता बढाने हेतु एक विशाल जागरूकता रैली का अयोजन किया गया।रैली में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, सामाजिक संगठनों एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के माध्यम से बाल श्रम छोड़ो, शिक्षा से नाता जोड़ोष तथा ष्हर बच्चे का अधिकार–शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानष ष बाल श्रम अपराध हैष बाल श्रम एक सामाजिक बुराई हैष जैसे संदेश दिये गए।इसके उपरान्त वृहद संगोष्ठी का अयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारियों, चाइल्ड लाइन प्रतिनिधियों एवं अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। वक्ताओं ने बाल श्रम के दुष्परिणामों, बच्चों के शिक्षा एवं संरक्षण के अधिकार तथा बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगोष्ठी में बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के विरूद्ध जन–जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक बचपन उपलब्ध कराना है। यह दिवस विश्व स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे बाल श्रम की किसी भी घटना की सूचना संबंधित विभागों को दें तथा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करें। सहायक श्रमायुक्त अयोध्या द्वारा मंच का संचालन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए विशेष अतिथि के तौर पर सहायक निदेशक कारखाना अनंत कुमार, जिला प्रोवेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, ए०एच०टी०यू० प्रभारी गौरीशंकर पाल,श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूपेन्द्र,गौरव गुप्ता, सत्येन्द्र प्रताप एवं शिव कुमार यादव, प्रशासनिक अधिकारी, पल्लवी दीक्षित जिला कोआर्डिनेटर चाइल्ड लाइन (1098) कविता मिश्रा अपराजिता सेवा संस्था (एन०जी०ओ०), वन स्टाप सेन्टर प्रभारी प्रभा पाल, वंदना तिवारी, व्यापार मण्डल अयोध्या से पंकज गुप्ता,विमल मिश्रा,विनय कटियार, राजेश चौहान एवं विभागीय कर्मचारी, जन सामान्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रतिभाग किया।सभी प्रतिभागियों ने बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण हेतु सामूहिक संकल्प भी लिया।

लता चौक पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के संयोजन में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।ज्येष्ठ मास के सातवें बड़े मंगलवार के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के संयोजन में नया घाट स्थित लता चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रामनगरी में उमड़ी श्रद्धा और भक्ति की धारा के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया।भंडारे का शुभारंभ मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास तथा महापौर गिरीश पति त्रिपाठी द्वारा हनुमानजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विश्व कल्याण की मंगलकामना के साथ किया गया। इस अवसर पर वातावरण जय श्रीराम और बजरंगबली के जयघोषों से गूंज उठा।जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित' ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भंडारे के लिए कई स्टॉल स्थापित किए गए हैं। 'एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के प्रसाद की व्यवस्था की गई' है यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है तथा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को लगातार आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जा रहे हैं।देर शाम तक चलने वाले इस विशाल भंडारे में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों एवं लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

'पाहरुआ कलां का ऐतिहासिक कछुआ तालाब बनेगा जैव विविधता संरक्षण का मॉडल केंद्र'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' जनसहभागिता, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विकास खंड मिर्जापुर के ग्राम पाहरुआ कलां स्थित ऐतिहासिक कछुआ तालाब का जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तालाब के संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं कछुओं के सुरक्षित आवास के विकास हेतु विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था हेतु नालियों को बड़े नाले से जोड़ा जाए, तालाब के चारों ओर पाथ–वे का निर्माण किया जाए तथा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन (प्रकृति आधारित समाधान) अपनाकर इसे एक आदर्श जैव विविधता संरक्षण स्थल के रूप में विकसित किया जाए उन्होंने व्यापक वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं प्राकृतिक आवास संरक्षण पर विशेष बल दिया। ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी ने कछुआ तालाब को क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण में जनसहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह स्थल केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि स्थानीय आस्था और प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने तालाब के पुनर्जीवन हेतु किए जा रहे प्रयासों के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का उल्लेख करते हुए कछुओं के धार्मिक एवं पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से चल रहे व्यापक स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान के परिणामस्वरूप तालाब का मूल स्वरूप पुनः उभरकर सामने आया है तथा आगामी दो माह में इसे और अधिक विकसित एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने ग्रामवासियों, युवाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों से इस संरक्षण अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवाओंकृप्रेम सरन शर्मा, ऋषि सिंह, देवसरन शर्मा, धर्मेन्द्र सिंह, रंजीत, अजय शर्मा, बदन सिंह एवं सुरजन सिंहकृको "कछुआ मित्र सम्मान" प्रदान कर सम्मानित किया गया वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी एवं लोक भारती महानगर संयोजक आलोक मिश्रा को भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की प्रतिमा भेंट कर उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। वरिष्ठ शिक्षाविद बृज किशोर शर्मा ने जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह भेंट कर ग्राम के विकास एवं तालाब संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समाजसेवी कृष्ण कुमार सिंह, दिलीप गुप्ता, वीरभान सिंह, करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, गंगा समग्र से मैथिलीशरण गुप्त, स्थानीय ग्रामवासी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि के पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सुखवीर सिंह, तहसीलदार सृजत कुमार, क्षेत्रीय वनाधिकारी विशाल रावत, खंड विकास अधिकारी धर्मेश चंद्र, कानूनगो सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला परियोजना अधिकारी डॉ. विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया।

श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में प्राप्त दान एवं चढ़ावे से आरोपों की निष्पक्ष हो जांच - शरद शुक्ला

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने आज थाना श्रीरामजन्मभूमि, अयोध्या में एक प्रार्थना पत्र देकर श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में प्राप्त दान एवं चढ़ावे के संबंध में विभिन्न माध्यमों से सामने आए आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत जांच कराए जाने की मांग की है।शरद शुक्ला ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि श्रीरामजन्मभूमि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है तथा मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान और चढ़ावा केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर के दान एवं चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर यदि किसी प्रकार की अनियमितता, गबन, धन के दुरुपयोग अथवा अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कराई जाए तथा यदि जांच में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा पदाधिकारी की संलिप्तता अथवा किसी संज्ञेय अपराध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।प्रार्थना पत्र में यह भी मांग की गई है कि जांच के दौरान लेखा अभिलेखों, बैंक विवरणों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। साथ ही जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर कराई जाए।शरद शुक्ला ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के विरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाना नहीं है, बल्कि जनमानस और करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़े विषय पर सत्य की स्थापना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन इस गंभीर विषय पर निष्पक्षता के साथ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

फाम,वाल प्लास्टिक व फाइबर भी भड़काते हैं आग – सीएफओ

अयोध्या।नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में अप्रैल से ही भारी संख्या में अग्निकांड की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारी की माने तो आग की घटनाएं छोटी–छोटी लापरवाही के चलते होती है जो बड़ी घटना का रूप धारण कर लेती है जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान होती है।इस संबंध मे जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण भले ही शार्ट सर्किट, गैस रिसाव, बैटरी में खराबी या लापरवाही हों।लेकिन इसके अलावा घरों और वाहनों में बढ़ते प्लास्टिक, फाइबर, फोम और अन्य कृत्रिम पदार्थ,आग को तेजी से फैलाने और धुएं की मात्रा बढ़ाने का काम कर रहे हैं।आग से बचाव हेतु आधुनिक सुविधाओं व आकर्षक सजावट के साथ सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान देना आवश्यक है। ताकि आग लगने की स्थिति में जान–माल के नुकसान को कम किया जा सके।उन्होंने बताया कि आजकल घरों और दफ्तरों में पीवीसी पैनल, फाइबर शीट, फाल्स सीलिंग और वाल प्लास्टिक, फाइबर, फोम और अन्य कृत्रिम पदार्थ आग को बहुत ही तेजी के साथ फैलाने और धुएं की मात्रा को भी बढ़ाने का करते हैं।बताया कि आजकल घरों तथा दफ्तरों में पीवीसी पैनल फाइबर शीट फाल्स सीलिंग और वाल क्लैडिंग का उपयोग तेजी से बढ़ा है। माड्यूलर फर्नीचर, लैमिनेट, फोम वाले सोफे, गद्दे और प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग पहले की तुलना में कहीं अधिक हो रहा है।इमारतों के रंग–रोगन में विभिन्न प्रकार की सिंथेटिक कोटिंग्स और सजावटी परतों का उपयोग भी बढ़ा है।ये सामग्री आमतौर पर आग लगने का कारण नहीं होतीं, लेकिन आग लगने के बाद उसे तेजी से फैलाने में मदद करती हैं।कई कृत्रिम पदार्थ जलने पर अत्यधिक गर्मी और घना धुआं पैदा करते हैं,जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।बंद व कम वेंटीलेशन वाली जगहों में ऐसी सामग्री आग को कुछ ही मिनट में पूरे हिस्से में फैला सकती है।बताया कि अधिकतर लोगों की मौत केवल जलने से नहीं होती,बल्कि आग लगने के चलते निकलने वाले जहरीले धुओं से भी लोगों की मौत हो जाती है।बताया कि पीवीसी, फोम, रबर और अन्य सिंथेटिक पदार्थ जलने पर खतरनाक गैसें निकलती हैं।इनमें कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोजन सायनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्जीन डाइआक्साइड जैसी जहरीली गैसें शामिल है।

हत्या की कोशिश के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। पुलिस ने हत्या की कोशिश के एक मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का संबल और तीन लकड़ी के डंडे बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, नौ जून को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एकराय होकर वादी के भाई और पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया था। आरोपियों ने लाठी–डंडों और लोहे की खंती से हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़ित की तहरीर पर थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अभिषेक और रामसमुझ निवासी अलगटपुर टोला महुआरी को गिरफ्तार कर लिया।

जिंदापुर में जमीन के विवाद में मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत

गोरखपुर, (संवाददाता)। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जिंदापुर गांव में जमीन के विवाद में मारपीट के मामले में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। सात जून की रात हुए विवाद में 62 वर्षीय रामा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी शनिवार देर रात मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता जयहिंद और संध्या देवी की तहरीर पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक पक्ष की ओर से जयहिंद ने 9 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें मारपीट, हाथ में असलहा लेकर जान से मारने की धमकी और रामा के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। दूसरे पक्ष ने भी बुजुर्ग रामा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि रामा की मौत की सूचना मिलते ही दूसरे पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। परिजन के अनुसार, सात जून की रात करीब 11 बजे जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। इस दौरान रामा के सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए और खून बहने लगा। परिजन उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को दोपहर करीब साढ़े पांच बजे शव गांव पहुंचा, जिसके बाद परिजन में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी और पांच पुत्रों को छोड़ गए हैं। स्थिति को देखते हुए पीपीगंज थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह और कैंपियरगंज थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई।

विश्व रक्तदाता दिवस पर गोरखपुर-बस्ती मंडल में 200 लोगों का रक्तदान

गोरखपुर, (संवाददाता)। विश्व रक्तदाता दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गोरखपुर–बस्ती मंडल में 200 लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की और महादानी बने। गोरखपुर शहर में तीन स्थानों एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक 94 लोगों ने रक्तदान कर दूसरों की जान बचाने का जज्बा दिखाया। एम्स में कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने शिविर का उदघाटन किया।इस दौरान कुल 34 महादानियों ने दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह ने रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र दिया। यहां 41 लोगों ने रक्तदान किया। आयोजन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अखिल विश्व गायत्री परिवार का विशेष सहयोग रहा। डॉ. बीके सुमन, शिवेंद्र विक्रम सिंह, महेंद्रनाथ चतुर्वेदी, डॉ. दीनानाथ सिंह, ज्ञानेंद्र ओझा आदि मौजूद रहे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शिविर का उद्घाटन ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अर्चना त्रिपाठी ने किया।

बीकापुर एसडीएम न्यायिक के पद पर राम प्रसाद त्रिपाठी ने संभाला कार्यभार

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। बीकापुर नव नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट राम प्रसाद तिवारी ने बीकापुर पहुंचकर एसडीएम न्यायिक नका कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने न्यायालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा अधिवक्ताओं से परिचयात्मक मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित कर वादकारी को कम से कम समय में न्याय प्रदान करना है । मालूम हो कि यहां तैनात रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह का स्थानांतरण रेजीडेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हो गया है। उनके स्थान पर राम प्रसाद तिवारी की तैनाती की गई है।

महिला एसओ ने किया योग अभ्यास

अयोध्या।महिला थाना परिसर मे मंगलवार को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ योगा अभ्यास किया।उन्होंने बताया महिला परिसर मे यह योगाभ्यास 21 जून तक चलता रहेगा।इस

मौके पर उनके अलावा महिला उप निरीक्षक सोनी, प्रिया, श्वेता राठौर, सहित विमलेश,सायरा बानू,करिश्मा दूबे,वंदना, प्रेया सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

'जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सड़कों पर दुर्घटना से बचाव हेतु

रिफ्लेक्टर, साइनेज आदि लगाया जाए। नेशनल हाईवे पर स्पीड साइनेज लगाएं। उन्होंने चिन्हित ब्लैक स्पॉट स्थलों पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सीतापुर–बरेली हाईवे पर ई–रिक्शा संचालन नियंत्रित करने तथा हाईवे पर ई–रिक्शा के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में जिलाधिकारी ने बरेली–सीतापुर मार्ग, अल्लाहगंज–जलालाबाद मार्ग तथा कटरा मार्ग के दुर्घटना संभावित स्थलों पर रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक निर्देश दिए।

एसएसपी ने छतिरवा नई अस्थायी पुलिस चौकी खोले जाने का दिया निर्देश

अयोध्या। मंगलवार को जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक सुदृढ़ एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने थाना पूराकलंदर क्षेत्र के तहत अस्थायी नवीन पुलिस चौकी ष्छतिरवाष के गठन का आदेश जारी किया है।बताते चले कि इस नई चौकी मे कुल 10 गांवों को शामिल किया गया है।जिनमें छतिरवा, अंतपुर, बभनगवां, चांदपुर कैल, सरैया, पाराकैल, दसौली, पोरा, बरवां और बेतौली शामिल हैं।पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मियों का मानना है कि नई चौकी के संचालन से क्षेत्र में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध होगी, अपराध नियंत्रण में मजबूती आएगी तथा आम जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

ब्लेज ब्लास्टर ने 20 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में बनाई जगह

भदोही, (संवाददाता)। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेनुपावर डिवीजन रेणुसागर के संयोजन में आदित्य बिड़ला इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल के मैदान पर चल रहे आरपीएल 2026 क्रिकेट के इलिमिनेटर मैच के रोमांचक मुकाबले में ब्लेज ब्लास्टर ने शानदार क्रिकेट मैच का प्रदर्शन करते हुए पॉवर पैंथर को 20 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्लेज ब्लास्टर की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाने का लक्ष्य रखा। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी पॉवर पैंथर की टीम 14.2 ओवर में आलआउट होकर 99 रन ही बना पाई। इस तरह ब्लेज ब्लास्टर की टीम ने 20 रन से विजयी हुई। ब्लेज ब्लास्टर की ओर से सुधांशु सिंह अपने टीम के लिये महत्वपूर्ण 4 विकेट चटका कर मैन ऑफ द मैच रहे। ब्लेज ब्लास्टर के टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।